

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-424 /2017

महेन्द्र कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.01.2016 (अनुलग्नक-10) एवं 29.11.2016 (अनुलग्नक-11) को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 27.01.2016 के द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्षीय एसीपी का लाभ स्क्रिनिंग की दिनांक 04.06.1988 से गणना करते हुए दिया गया है एवं आदेश दिनांक 29.11.2016 से अपीलार्थी के मामले में पुनः परीक्षण कर अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 07.09.1988 से नियमित होना मानते हुए एसीपी का लाभ उसी दिनांक से सेवा की गणना करते हुए दिया जाना उचित माना है। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 12.07.1985 के द्वारा हुई थी एवं अपीलार्थी ने दिनांक 13.07.1985 को कार्य ग्रहण किया था। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.06.1988 जारी किया, जिसमें यह निर्देश दिये गये कि पंचायत समितियों में दिनांक 31.12.1985 तक नियुक्त अध्यापकों की समीक्षा (स्क्रीनिंग) की जाकर उनकी सेवाएं नियमित की जावे। उपरोक्त परिपत्र के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जिला परिषद द्वारा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कर अपीलार्थी को नियमित किया गया एवं अपीलार्थी को दो वर्ष के परीविक्षाकाल में रखा गया। नियमितिकरण का आदेश दिनांक 07.09.1988 को जारी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने तृतीय श्रृंखला अध्यापकों की अस्थायी वरीयता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का चयन दिनांक 13.07.1987 मानते हुए अपीलार्थी को वरिष्ठता दी गयी। अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान

का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.07.1985 मानते हुए प्रदान किया गया था। बाद में 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं दिया जाकर स्क्रीनिंग की दिनांक 04.06.1988 से सेवा की गणना करते हुए प्रदान किया गया, जो उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :-

"It is therefore most humbly prayed that this appeal may kindly be allowed and call for the record relating to the case and after examining the same the impugned orders dated 27.1.2016 (Annex-10) and 29.11.2016 (Annex-11) may kindly be quashed and set aside and further bedirected to the respondents to count his services from the date of initial appointment i.e. 13.7.1985 for the purpose of third selection grade/ACP and consequence arrears be also granted with interest of 9% P.A."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह मद प्रतिपादित किया है कि चयनित वेतनमान/एसीपी हेतु सेवा की गणना नियमित नियुक्ति तिथि से ही की जावेगी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति कुचामन के आदेश दिनांक 12.07.1985 के द्वारा अस्थाई तौर पर की गई थी। जिसे जिला परिषद नागौर के पत्रांक-1240 दिनांक 11.05.1988 व एक अन्य पत्रांक-1333 दिनांक 04.06.1988 के द्वारा नियमित किये जाने पर पंचायत समिति कुचामन सिटी द्वारा इस आशय का आदेश दिनांक 07.09.1988 को जारी किया गया। पंचायत समितियों द्वारा की जाने वाली अस्थाई नियुक्तियों के सम्बन्ध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 24.10.2000 के अनुसार शासन के विभिन्न आदेशों के हवाले से ऐसे कार्मिकों के लिये चयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी होने की तिथि से ही किया जाना आदेशित किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग तिथि उसके सेवाअभिलेख के अनुसार दिनांक 04.06.1988 अंकित होने से तदनुसार ही एसीपी का लाभ दिया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावें।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही चयनित वेतनमान का लाभ देय है। अपीलार्थी ने सेवा में बिना किसी ब्रेक के प्रथम नियुक्ति की दिनांक 13.07.1985 से लगातार कार्य किया है। अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 13.07.1985 मानते हुए दिया गया। ऐसे में 27 वर्षीय

चयनित वेतनमान का लाभ भी इसी क्रम में दिनांक 13.07.1985 से दिया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी रूप से हुई थी। बाद में आदेश दिनांक 07.09.1988 के द्वारा स्क्रीनिंग किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी। एसीपी का लाभ नियुक्ति दिनांक से ही देय होता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ गलत रूप से दिया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी गलत रूप से सेवा की गणना करते हुए दिया जाना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है:—

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :—

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9,

18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं सलेक्शन कमेटी द्वारा चयन के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा चयन के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी एसीपी एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)